



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935

No. 47]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2014

सं. टीएमपी/53/2007—जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/53/2007—जेएनपीटी

कोरम:

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2014 के 10वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2. जेएनपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएमपी/53/2007—जेएनपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011, जिसे 24 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण जेएनपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने जेएनपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता, पिछली बार अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक विस्तारित की थी।

3. जेएनपीटी द्वारा अपने दरमान के संशोधन के लिए अपने पत्र दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर संबद्ध पत्तन उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार-विमर्श के लिए लिया गया था। इस मामले पर संयुक्त सुनवाई 30 अगस्त, 2013 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, हमारे पत्र दिनांक 4 जून, 2013 द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपने पत्रों दिनांक 12 सितम्बर, 2013, 20 सितम्बर, 2013 और 25 सितम्बर, 2013 द्वारा अपना जवाब भेजा था। इसके अलावा, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 द्वारा अपने मसौदा दरमान में कुछ संशोधनों/परिवर्धनों का प्रस्ताव किया है। जेएनपीटी से उसके विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रत्युत्तर और मसौदा दरमान में प्रस्तावित और संशोधनों पर जांच की जा रही है और इस प्राधिकरण द्वारा विचार कर अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा।

4. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं.

टीएमपी/21/2009—डब्ल्यूएस दिनांक 20 दिसम्बर, 2013, जिसे जी. सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, द्वारा प्रषुल्क दिषानिर्देश, 2005 की वैधता को विस्तारित किया है।

5. चूंकि मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो चुकी है और अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए इस मामले हेतु अपेक्षित समय पर विचार करते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि प्रषुल्क दिषानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण जेएनपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिषे 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिषे निर्धारित किए जाने वाले प्रषुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असाधारण/143/13]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2014

**No. TAMP/53/2007-JNPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No. TAMP/53/2007-JNPT**

#### QUORUM

- (i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

#### ORDER

(Passed on this 10th day of January, 2014)

This relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the JNPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/53/2007-JNPT dated 18 February, 2011 which was notified in the Gazette of India on 24 March, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of JNPT twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of JNPT till 31 December, 2013 *vide* its Order dated 29 October, 2013.

3. The proposal filed by the JNPT *vide* its letter dated 5 October, 2012 and 19 December, 2012 for general revision of its Scale of Rates is taken on consultation with the concerned port users/user organisations. Joint hearing in this case was held on 30 August, 2013. As agreed at the joint hearing, the JNPT has furnished its reply *vide* its letter dated 12 September, 2013, 20 September, 2013 and 25 September, 2013 to the queries raised *vide* our letter dated 4 June, 2013. Further, the JNPT *vide* its letter dated 23 December 2013 has proposed some modifications/additions in its draft Scale of Rates. The response of the JNPT through its various letters and the further modifications proposed in the draft SOR is under scrutiny and it will take some more time for the case to mature for consideration of the Authority.

4. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March, 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 *vide* its Order No. TAMP/21/2009-WS dated 20 December, 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December, 2013 *vide* G. No. 340.

5. Since the validity of the existing SOR expired on 31 December, 2013 and recognizing that it will take some more time for the case to mature for final consideration and also recognising that the validity of the Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March, 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the JNPT from the date of its expiry till 31 March, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Ext./143/13]